ch-3

6/10/2022
PANKAJ
Page No.:
Date : / /

(3.) शुरुआती कदम :—

⇒ सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं के विकल्प का चयन किया। इसके पीछे विचार था कि भारत सरकार अपनी ओर से एक दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें अगले पाँच वर्षों के लिए उसकी आय और व्यय की योजना होगी।

⇒ इस योजना के अनुसार केन्द्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को दो हिस्सों में वर्गीकृत किया गया। एक हिस्सा गैर योजना व्यय का था। इसके अन्तर्गत वार्षिक आधार पर दैनंदिन मदों पर खर्चा करना था। दूसरा हिस्सा योजना-व्यय का था योजना में तय की गयी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे पाँच वर्ष की अवधि में व्यय करना था।

(i) प्रथम पंचवर्षीय योजना :—

⇒ सन् 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ तथा इसी वर्ष नवम्बर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया।

⇒ प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल कृषि-क्षेत्र पर दिया गया था। इसी योजना के अन्तर्गत बाँध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। साथ ही भूमि-सुधार पर भी बल दिया गया।

⇒ योजनाकारों का मूलभूत लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊँचा करना था। यह तभी संभव था जब लोगों की बचतें उनके खर्चों से अधिक हो। सन् 1950 के दशक में खर्च का स्तर भी बहुत नीचे था।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में इससे कहीं अधिक बचत की आशा थी।

(ii) औद्योगीकरण की तेज रफ्तार :—

⇒ दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में भारी उद्योगो के विकास पर जोर दिया गया। पी. सी. महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियो और योजनाकारों के एक दल ने यह योजना तैयार की।

⇒ सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया। संरक्षण की इस नीति से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ने में पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई। औद्योगीकरण पर दिए गए बल ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया।

(4.) मुख्य विवाद :—

⇒ जे. सी. कुमारप्पा जैसे गाँधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया था जिसमें ग्रामीण औद्योगीकरण पर बल दिया गया था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में अत्यन्त सुविचारित और सशक्त ढंग से उठाई थी।

⇒ कई लोगों का मत था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तीव्र किए बिना गरीबी से छुटकारा नहीं मिल सकता इनका तर्क था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति अपनायी गयी थी लेकिन औद्योगिक विकास की दिशा में कोई विशेष प्रयास नहीं किये गये।